राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.10(32)न्याय/2016/पार्ट । **जयपुर, दिनांक** 21.9.22

–:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::–

राजस्थान उच्च न्यायालय को पेपरलेस कोर्ट बनाने हेतु हार्डवेयर आईटम क्रय करने हेतु लेखामद 2014–00–105–01–00–62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय मद (राज्यनिधि) (स्कीम) में चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत राशि रू. 255.68 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत किया जाता है। उक्त राशि IFMS पर Online अपलोड कर दी गयी है।

उक्त स्वीकृति वित्त व्यय–5 विभाग की आई.डी. संख्या 102204589 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांकः–III/(1)B/Budget/2017-18/डिजीटाईजेशन/1965 दिनांक 26.07.2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय–5) शासन सचिवालय,जयपुर।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

21.9.22

(अंकित रमन)
सयुक्त शासन सचिव